AADHAAR

VIRAT VAIBHAV, Delhi, 12.7.2017
Page No. 5, Size:(17.08)cms X (12.36)cms.

सहायता भ्रष्टाचार समाप्त कर 50,000 करोड़ रुपए की बचत की

भ्रष्टाचार समाप्त करने में आधार प्रभावी उपाय

एजेंसी ■ नई दिल्ली

सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से देश के गरीब और वंचित समुदायों को आधार सेवाएं उपलब्ध कराने में ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के प्रभाव और प्रगति के बारे में बताने के लिए सीएससी एसपीवी ने 'सीएससी के जरिए आधार सेवाएं- एक असाधारण पहल ' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की।

केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि जमीनी स्तर पर लोगों को महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में उद्यमशील ग्रामीण स्तर के उद्यमियों के प्रयास सराहनीय हैं और आधार अब भ्रष्टाचार मिटाने के प्रभावी उपाय के रूप में उभर कर सामने आया है। यहां एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, आधार भ्रष्टाचार मिटाने में प्रभावी उपाय है। हमने भ्रष्टाचार समाप्त कर 50,000 करोड़ रुपए की बचत की है।' उन्होंने आशा व्यक्त की कि समय-समय पर ग्रामीण स्तर के उद्यमी (वीएलई) आगे आएंगे और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने में सरकार की मदद करेंगे।' मंत्री ने कहा कि, 'मुझे सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) एवं ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) से काफी उम्मीद है। हमारे वीएलई भारत में परिवर्तन लाने वाले हैं। सीएससी ने देश के दस लाख लोगों को रोजगार दिया है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में एक करोड़ लोग सीएससी में कार्य करेंगे। सरकारी अभियानों के अन्तर्गत नागरिकों को जागरूक बनाने में वीएलई की क्षमता को दोहराते हुए विधि मंत्री ने कहा, मुझे यह जानकार काफी प्रसन्नता हुई है कि नगदी रहित अभियान में वीएलई ने दो करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने कहा, 'हाल ही में केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हथकरघा उत्पादों के विस्तार के लिए वीएलई का सहयोग मांगा था।

सरकार के सभी विभाग अपनी सेवाओं के लिए वीएलई को शामिल करना चाहते हैं। सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से देश के गरीब और वंचित समुदायों को आधार सेवाएं उपलब्ध कराने में ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के प्रभाव और प्रगति के बारे में बताने के लिए सीएससी एसपीवी ने 'सीएससी के जरिए आधार सेवाएं- एक असाधारण पहल ' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लगभग 600 वीएलई को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यूआईडीएआई, उर्वरक विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अजय प्रकाश साहनी ने कहा, 'सरकार के समर्थन विशेष रूप से माननीय मंत्री के सहयोग से सीएससी अभियान को नई पहचान मिली है।